संख्या सर्वकालिक नहीं हो सकती और इसमें घटत-बढ़त अनिवार्य है। औसत आयु में वृद्धि के साथ-साथ बढ़ती ग्रामीण बेरोजगारी के फलस्वरूप इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में पात्रताधारियों की संख्या 1,01,025 बढ़ी है, लेकिन इसके उपरांत भी राजस्थान सरकार की निरंतर मांग के बावजूद केन्द्र सरकार ने गेहूं का कोटा नहीं बढ़ाया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के द्वारा मांग करता हूं कि नव चयनित पात्रताधारी वृद्धों के साथ इस अन्यायपूर्ण भेदभाव को अविलंब समाप्त किया जाना चाहिए और बढ़ी हुई संख्या के लि 12,123 मीट्रिक टन का अतिरिक्त आवंटन किया जाना चाहिए।

धन्यवाद।

Demand to Rehabilitate the Farmers displaced by establishment of Bhilai Steel Plant

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं भिलाई स्टील प्लांट से प्रभावित किसानों के हितों की रक्षा तथा उनके बच्चों की भिलाई स्टील प्लांट में प्राथमिकता पर नौकरी दिए जाने के बारे में इस विशेष उल्लेख द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई स्टील प्लांट के निर्माण के समय से सामुदायिक विभाग 16 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के निर्माण कार्य में अपनी भागीदारी निभाता आ रहा है। उस वक्त, निर्माण कार्यों के लिए, विभाग की ओर से बहुत कम राशि स्टील प्लांट को इन गतिविधियों द्वारा आवंटित की गई जब कि निर्माण के समय यह कहा गया था कि जो ग्राम, भिलाई स्टील प्लांट के अंदर आर्थिक रूप से प्रभावित होंगे, उन सभी ग्रामों के लिए विकास कार्य की देखरेख भिलाई स्टील प्लांट करेगा। भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क पत्थर की आपूर्ति दल्ली राजहरा माईंस से की जाती है। बालोद का आत्माबाद टैंक किसानों की 4 लाख एकड़ सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति करता था, उन किसानों को यह कहा गया कि यदि इसका आधा पानी भिलाई स्टील प्लांट को उपलब्ध कराया जाए, तो उन प्रभावित किसानों के बच्चों को नए स्टील प्लांट में नौकरी दी जाएगी। दल्ली राजहरा से भिलाई तक वाया बालोद-गुन्डरदेही रेलवे लाइन बनाई गई है, इसके लिए भी हजारों किसानों की जमीन इस शर्त पर ली गई है कि उन किसानों के बच्चों को भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी दी जाएगी, किन्तु इस आश्वासन को भी पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया है, साथ ही, पानी के अभाव में किसानों की फसल भी बरबाद हो रही है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो गांव, भिलाई स्टील प्लांट से विस्थापित हुए हैं, उनके विकास के लिए भिलाई स्टील प्लांट एवं दल्ली राजहरा माईंस को सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाए तथा सामुदायिक विकास का क्षेत्र 50 किलोमीटर किया जाए। इसके अतिरिक्त भिलाई स्टील प्लांट में दुर्ग जिले के बेरोजगारों को योग्यतानुसार नौकरी दी जाए। अक्सर आए दिन छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को open vacancy के नाम से नौकरी दी जाती है, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए और दुर्ग एवं छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षित बच्चों को उनकी योग्यतानुसार नौकरी दी जाए। धन्यवाद।

श्री रामाधार कश्यप (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं अपने को इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं अपने को इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूं।

Need to provide Financial Assistance to palm industries in Tamil nadu

SHRI C. PERUMAL (Tamil Nadu): Sir, there are more than five hundred khadi and village industries in our country. The main industry is palm industries in Tamil Nadu. These palm industries are situated in the following regions of Tamil Nadu, namely, Krishnagiri, Dharmapuri, Salem, Erode,Coimbatore, Chengalpattu, Cuddalore, Pudukottai, Madurai, Ramanathapuram,

Thirunelveli and Kanyakumari. They were producing Palm Juice, Palm Jaggery, Palm Candy, Neera, Palmta, Palm Cola, etc., from the palm trees. Palm sugar is generally used by diabetic patients, pregnant women and mill labourers. This keeps them very healthy. Previously, palm fibre used to be manufactured in Colachel, Kanyakumari District in Tamil Nadu and was being exported from the tuticorin Harbour. The Government of India earned nearyly Rs. 20 crores of foreign exchange. Madhavaram at Chennai, Mathur at Krishnagiri District, Kalinganaickahpalayam at Coimbatore District, Kadapakkam at Chengleput District were having manufacturing units of Palm Candy, Palm Jaggery, Palm Sugar, Palmta, Palm Cola, Palm Chocolate and handicrafts. They used to get financial assistance from the Khadi and Village Industries Commission through the State Government. Thousands of labourers of these backward districts were getting employment opportunities. Due to the decision of the KVIC to stop the financial assistance from 1998-1999 resulting in closure of these industries, thousands of labourers have lost their employment.

Sir, through this House, I request the Government to revive the earlier scheme and provide the financial assistance to these units. Grouphousing and old-age pension for palm labourers may be introduced by the Central Government to save thousands of labourers depending only on these industries.

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (Madhya Pradesh): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI S. ANBALAGAN (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI UDAY PRATAP SINGH): Shrimati Syeda Anwara Taimur; not present. Ms. Pramila Bohidar.

Concern over high maternal mortality

MS. PRAMILA BOHIDAR (Orissa): The high Maternal Mortality Rate in India calls for immediate measures to check this menace. The National figure of Maternal Mortality Rate is 301 per one lakh of live births in a State like Orissa; it may be more in the case of some other States.

To check this menace, we should expand the scope of delivery and proper post-natal care. The role fo ANM, ASHA and Anganwadi workers is vital for cent per cent registration of pregnant cases and arranging pre and post-natal services at their doorsteps, including arrangements for institutional delivery or ensuring delivery by shelled attendants. All the posts of Doctors and Paramedical staff like that of ANM and LHV need to be filled up. It is seen that some sub-centres still go without ANMs.

One of the most important factors contributing to the high mortality is widespread malnutrition among women. The recent National Family Health Survey-III has revealed widespread under-nutrition among women and children and high maternal mortality. One-third of the women in this country are malnourished and over half of the women are anaemic.

The high rate of Infant Mortality also constitutes under-nourished, under-weight and anaemic children. Recently, on the eve of the World Food Day, it was said by experts that India is the most starving country in the world and women and girls are affected the most.

In view of this, I request the Government and the Ministry of Health to give special attention to this issue of women health and check the MMR and IMR.